



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रविष्टि सूचना

शिमला-171004, 6 मार्च, 2000

संख्या 1-12/2000-बि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज

दिनांक 6 मार्च, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभामें पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनायें राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2000 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000

31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संचाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2000 है।

संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां जिनका योग 3,86,13,02,573 रुपये (तीन अरब, छयासी करोड़, तेरह लाख, दो हजार, पांच सौ तेहतर रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1999-2000 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभावों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए 3,86,13,02,573 रुपये की और राशि जारी करना।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मौलिक संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और (राजस्व) निर्वाचन	4,84,36,850	—	4,84,36,850
2	राज्यपाल और मन्त्री (राजस्व) परिषद्	1,58,10,000	3,08,000	1,61,18,000
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	83,07,000	4,16,500	87,23,500
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	2,000	24,30,000	24,32,000
	(पूँजी)	1,000	—	1,000
5	भू-राजस्व (राजस्व)	1,98,72,300	—	1,98,72,300
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	3,42,87,330	28,67,123	3,71,54,453
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	—	2,88,961	2,88,961
	(पूँजी)	9,41,00,000	—	9,41,00,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला (राजस्व)	79,35,39,958	52,34,197	79,87,74,155
	और संस्कृति (पूँजी)	4,24,29,000	1,29,65,107	5,53,94,107
9	चिकित्सा और परिवार (राजस्व) कल्याण	7,60,80,000	6,14,916	7,66,94,916
	(पूँजी)	3,07,32,000	—	3,07,32,000
10	लोक निर्माण (पूँजी)	4,66,60,687	79,67,313	5,46,28,000
11	कृषि (राजस्व)	—	12,793	12,793
	(पूँजी)	4,72,00,000	—	4,72,00,000
12	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व) नियंत्रण	4,34,00,000	—	4,34,00,000
	(पूँजी)	51,80,000	—	51,80,000
13	भूमि और जल संरक्षण (राजस्व)	2,92,64,600	—	2,92,64,600
	(पूँजी)	4,25,000	—	4,25,000
14	पशुपालन और दुग्ध (राजस्व) विकास	6,89,61,000	—	6,89,61,000
15	मत्स्य (राजस्व)	24,08,000	—	24,08,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	—	13,58,268	13,58,268
	(पूँजी)	70,000	—	70,000
17	मड़कें और पुल (पूँजी)	5,13,93,386	35,77,614	5,49,71,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व) (पूंजी)	30,17,53,800 —	20,180 4,92,981	30,17,73,980 4,92,981
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित) (राजस्व)	40,01,000	—	40,01,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	1,000	—	1,000
21	सहकारिता (पूंजी)	11,30,00,000	—	11,30,00,000
25	सड़क, जल परिवहन और नागर विमानन (राजस्व) (पूंजी)	25,00,000 13,47,00,000	—	25,00,000 13,47,00,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन (राजस्व)	25,00,000	—	25,00,000
27	श्रम और रोजगार (राजस्व) (पूंजी)	—	1,19,450 5,92,520	1,19,450 5,92,520
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास (राजस्व) (पूंजी)	39,44,43,000 34,94,43,000	—	39,44,43,000 34,94,43,000
29	वित्त (राजस्व) (पूंजी)	64,50,61,121 —	14,20,43,618	64,50,61,121 14,20,43,618
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण (पूंजी)	16,10,00,000	—	16,10,00,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व) (पूंजी)	10,38,14,000 92,16,000	—	10,38,14,000 92,16,000
	कुल जोड़	3,67,99,93,032	18,13,09,541	3,86,13,02,573
	(राजस्व)	2,59,44,42,959	1,36,70,388	2,60,81,13,347
	(पूंजी)	1,08,55,50,073	16,76,39,153	1,25,31,89,226

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

प्रेम कुमार धूमल,
पृष्ठा मन्त्री।

शिमला :

6 मार्च, 2000

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[वित्त विभाग फाईल संख्या वित्त-ए-सी (2) 19/99]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2000

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2000.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2000.

Short title

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 3,86,13,02,573 (Three hundred eighty six crores, thirteen lakhs, two thousand, five hundred and seventy three rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1999-2000 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of a further sum of Rs. 3,86,13,02,573 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1999-2000.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Demand No.	2 Services and purposes		3		
			Sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	4,84,36,850	—	4,84,36,850
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	1,58,10,000	3,08,000	1,61,18,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	83,07,000	4,16,500	87,23,500
4	General Administration	(Revenue)	2,000	24,30,000	24,32,000
5	Land Revenue	(Capital)	1,000	—	1,000
6		(Revenue)	1,98,72,300	—	1,98,72,300
7	Excise and Taxation	(Revenue)	3,42,87,330	28,67,123	3,71,54,453
8	Police and Allied Organisations	(Revenue)	—	2,88,961	2,88,961
9		(Capital)	9,41,00,000	—	9,41,00,000
10	Education, Sports, Arts and Culture	(Revenue)	79,35,39,958	52,34,197	79,87,74,155
11		(Capital)	4,24,29,000	1,29,65,107	5,53,94,107
12	Health and Family Welfare	(Revenue)	7,60,80,000	6,14,916	7,66,94,916
13		(Capital)	3,07,32,000	—	3,07,32,000
14	Public Works	(Capital)	4,66,60,687	79,67,313	5,46,28,000
15	Agriculture	(Revenue)	—	12,793	12,793
16		(Capital)	4,72,00,000	—	4,72,00,000
17	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	4,34,00,000	—	4,34,00,000
18		(Capital)	51,80,000	—	51,80,000
19	Soil and Water Conservation	(Revenue)	2,92,64,600	—	2,92,64,600
20		(Capital)	4,25,000	—	4,25,000
21	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	6,89,61,000	—	6,89,61,000
22	Fisheries	(Revenue)	24,08,000	—	24,08,000
23	Forest and Wild Life	(Revenue)	—	13,58,268	13,58,268
24		(Capital)	70,000	—	70,000
25	Roads and Bridges	(Capital)	5,13,93,386	35,77,614	5,49,71,000
26	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	30,17,53,800	20,180	30,17,73,980
27		(Capital)	—	4,92,981	4,92,981
28	Social Security and Welfare (including Nutrition)	(Revenue)	40,01,000	—	40,01,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development (Revenue)	1,000	—	1,000
21	Co-operation (Capital)	11,30,00,000	—	11,30,00,000
25	Road, Water (Revenue)	25,00,000	—	25,00,000
	Transport and Civil (Capital)	13,47,00,000	—	13,47,00,000
	Aviation			
26	Tourism and Hos- (Revenue)	25,00,000	—	25,00,000
	pitality Organisation			
27	Labour and (Revenue)	—	1,19,450	1,19,450
	Employment (Capital)	—	5,92,520	5,92,520
28	Water Supply, (Revenue)	39,44,43,000	—	39,44,43,000
	Sanitation, Housing (Capital)	34,94,43,000	—	34,94,43,000
	and Urban Develop- ment			
29	Finance (Revenue)	64,50,61,121	—	64,50,61,121
	(Capital)	—	14,20,43,618	14,20,43,618
30	Loans to Govern- ment Servants (Capital)	16,10,00,000	—	16,10,00,000
31	Tribal Development (Revenue)	10,38,14,000	—	10,38,14,000
	(Capital)	92,16,000	—	92,16,000
	Grand Total	3,67,99,93,032	18,13,09,541	3,86,13,02,573
	(Revenue)	2,59,44,42,959	1,36,70,388	2,60,81,13,347
	(Capital)	1,08,55,50,073	16,76,39,153	1,25,31,89,226

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1999-2000.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 6th March, 2000.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-C(2)19/99]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2000, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.